भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2343
गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)

जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रोजगार पैकेज

2343. श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या जम्मू-कश्मीर में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी से निपटने और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 2002-2005 की योजना की तर्ज पर एक विशेष रोजगार पैकेज स्वीकृत किया जाएगा**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के युवाओं सहित) सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकार के श्रम और रोजगार विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसरों की सुविधा प्रदान करने और लोक सेवाओं में पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जम्मू-कश्मीर के युवाओं में बेरोजगारी की चुनौती का समाधान किया जा सके। जम्मू और कश्मीर सरकार स्वरोजगार और उद्यमिता संवर्धन योजनाओं की एक श्रृंखला को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर स्वरोजगार योजनाएं (जेकेएसईएस) शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आय सृजक इकाइयों की स्थापना के लिए बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण और सब्सिडी सहित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, मिशन यूथ पहलों (मुमकिन, तेजस्विनी, परवाज, स्पूरिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव और पर्यटन ग्राम विकास कार्यक्रम), मिशन युवा आदि सहित कई योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार के श्रम और रोजगार विभाग ने प्रमुख पहल "मिशन युवा" भी शुरू की है, जो स्टार्ट-अप, छोटे उद्यमों और अभिनव आजीविका उद्यमों का समर्थन करके अगले पांच वर्षों में लगभग 4.25 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य के साथ युवाओं के बीच उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहता है। 8 महीने की अवधि के भीतर इसकी शुरुआत के बाद से, स्वरोजगार/उद्यमिता के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लाभार्थियों के बीच 900 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

*****